LOK SABHA

Friday, April 28, 1972/Vaisakha 8, 1894 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Lead Bank Scheme

*601. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the Lead Bank Scheme started in December, 1969, has made any headway in opening new branches in the rural areas of the country and providing banking facilities to the masses ;

(b) if so, the number of branches opened under the Scheme, State-wise since its inception :

(c) whether any annual target is fixed under the Scheme ; and

(d) whether there is any gap in the actual performance and if so, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI) : (a) to (d). A statement is placed on the Table of House.

Statement

Since the commencements of the Lead Bank Scheme in January 1970 to the end of January, 1972, the banks in the public sector have opened 3498 new offices. Of these 2351 are located in rural and 575 in semi-urban areas. The pace of branch expansion of Commercial Banks has gained impetus from the operation of the lead bank scheme. The quick surveys carried out by the lead banks in their respective districts have helped identification of centres requiring banking facilities urgently. Regional meetings were convened by Reserve Bank to speed up and facilitate the location of growth centres thrown up by the surveys made by the banks. Such meetings have held at Madras, Calcutta, Patna, Kanpur, Bhopal, Delhi, and Jaipur. Besides the banks themselves have held meetings at district levels to draw up programmes for extending branch network to centres identified by them.

It is envisaged that in the three year period 1972-74 about 5000 new offices will be opened and the banks have been asked to prepare their plans accordingly. Keeping in view the limitations of their resources the progress of branch expansion so far has not been unsatisfactory.

A Statement showing the number of branches opened by the commercial banks Statewise is attached.

Statement

State/Union Territories	As on 31.12.69	As on 31.1.72	New offices opened between 31.12.69 and 31.1.72
1 2	3	4	5
1. Andhra Pradesh	618	923	305
2. Assam*	90	160	70
3. Bihar	309	510	201
4. Gujart	840	1194	354
5. Haryana	191	284	93
6. Himachal Pradesh	48	103	55
7. Jammu & Kashmir	48	107	59
8. Kerala	648	919	271
9. Madhya Pradesh	362	646	284

1	2	3	4	5
10.	Maharashtra	1203	1612	409
11.	Mysore	857	1203	346
12.	Nagaland	4	5	1
13.	Orissa	111	187	76
14.	Punjab	417	629	212
15.	Rajasthan	393	559	166
16.	Tamil Nadu	1110	1447	337
17.	Uttar Pradesh	817	1275	458
18.	West Bengal	537	736	199
19.	Manipur	2	6	4
20.	Tripura	6	12	6
21.	Union Territories	439	559	120
	* Including Meghalaya and Mizoram.			
	Total	9050	13076	4026

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR : From the statement, it appears that the banks plan to open new branches and have been asked to prepare plans accordingly. May I know if some public representatives will also be associated while the plans are drawn up or will it be only a one-way traffic ?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : While finalising the concept of the lead banks at the stage of drafting of the report, we do take some people from the universities, from the educational line and from public life also and take their help.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR : Since the reply is in the affirmative, may I know if the banking authorities will take into confidence members of Parliament and of the Assemblies before drawing up plans for the future ?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : It is a very good question. I think we as representatives of the public go to our constituencies and the areas where the lead banks will operate and give our ideas there. In case members have any constructive suggestions, we can take them up here also.

श्री सरजू पांडे : क्या सरकार ने ऐसा आदेश दिया है कि उन इलाकों में, जहां बाढ़-ग्रस्त और सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, एडवांस न दिये जायें, खास तौर पर काश्तकारों को ? जिन इलाकों में बाढ़ आई हैं या सूखा पड़ा हुआ है, वहां बैंक कर्जे नहीं दे रहे हैं। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का कोई ऐसा आदेश है कि जहां बाढ़ या सूखा है, वहां कृषकों को कर्जे न दिये जायें।

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : One of the factors which the lead bank scheme has emphasised is to give special facilities to the neglected sectors and areas which require maximum assistance. We shall examine the particular point which the hon. member has made and do what we can if such a thing arises.

SHRI R. S. PANDEY : It is mentioned in the statement :

> "Keeping in view the limitations of their resources, the progress of branch expansion so far has not been unsatisfactory."

At the same time, they have plans to open 5,000 new offices in the period 1972-74. How do these two things go together ?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : They are very compatible. If he will go through the entire statement, he will realise that the present position is that a number of new branches have been opened recently. I dare say that the number of branches which have been opened recently compare favourably with the number of such branches in any developing country. The target of 5,000 is for 1972-74.

श्री अरविन्द नेताम : चूंकि आदिवासियों की जमीन को नीलाम नहीं किया जा सकता है, इसलिये क्या बैंक इस अड़चन को देखते हुए आदिवासियों को लोन देने में असमर्थ हैं ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह तो मैं नहीं कहूंगी कि बैंक आदिवासियों को लोन देने में असमर्थ हैं, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगी कि नई शाखाएं खोलने का पूरा उद्देश्य यही है कि आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को, या पिछड़े क्षेत्रों की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाये,

जहा बैंकिंग की सुविधायें नहीं है और उनको हर तरह की सुविधायें प्रदान की जायें ।

SHRI SUBODH HANSDA : The Planning commission has declared about 200 districts throughout the country as industrially backward. Will priority be given to the opening of branch offices in all these areas ?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : Neglected and backward areas are being treated on a priority basis.

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या मन्त्री महोदय के पास इस तरह की शिकायतें आई है कि नई ब्रांचिज खुलने के बावजूद गरीबों को कर्जा नही दिया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री नेगी ।

श्री प्रताप सिंह नेगी : क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा सर्कुलर निकाला गया है कि जो लोग बैंको के साथ हिन्दी मे पत्र-व्यवहार करे, या हिन्दी मे चैक दें, उनको पैसा न दिया जाये ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह प्रश्न नही उठता है ।

श्री मुल्की राज सैनी : क्या सरकार का कोई ऐसा आदेश है कि ट्रैक्टर वगैरह के कर्जे उन गावो के लोगो को न दिये जाये, जो कच्ची सड़क पर पड़ते हैं, जो पक्की सड़क से दूर है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मिनिस्टर साहब से इस बारे में बात कर लें । यह प्रश्न इसमें नहीं पैदा होता है । यह प्रश्न नई ब्रांचिज खोलने के बारे मे है ।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : क्या मंत्री महोदया यह विचार करेंगी कि किसानों या ग्रामीण क्षेत्रों को जो फेसिलिटीज दी जायें, वे कम इंट्रैस्ट पर दी जायें । जहां तक मार्गेज करने का प्रश्न है, किसान मार्गेज नहीं कर पाता है और इसलिये बैंकिंग फेसिलिटीज से लाभ नहीं उठा पाता है । क्या मंत्री महोदया इसको ध्यान में रखकर . . .

MR. SPEAKER : It is a suggestion for action.

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY : This is for banking facilities in the rural areas.

MR. SPEAKER : It is not a question.

श्री भागीरथ भवर : मंत्री महोदय ने बताया है कि बैंको की शाखायें भिन्न भिन्न प्रदेशों मे खोली जा रही है । कई को-आपरेटिव बैंको की शाखाये काम कर रही हैं, लेकिन उनके माध्यम से किसानों को कर्ज नहीं मिल पाता है और कई तरह की दिक्कतें आती है । मैं यह जानना चाहता हू कि ये जो बैंक खोले जायेंगे, उनके खोलने का आधार क्या है । वे किन स्थानों पर खोले जायेंगे ? क्या वे जनसंख्या के आधार पर खोल जायेंगे या कुछ निर्धारित स्थानों पर खोले जायेंगे ? इस बारे मे क्या नीति निर्धारित की गई है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, यह बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है माननीय सदस्य ने । इसके विशेष कई पहलू है और कई उनके आधार पर तथा नीति के आधार पर यह बैंक खोले गये है । सबसे प्रमुख यह है कि वह इलाके जहा पर कि बैंकिंग की सुविधा होनी चाहिए और जो इस समय नही है वहा पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाय । तो इसके लिये बाकायदा सर्वे वगैरह करते है और लोकेशन वगैरह करने के उपरान्त यह सारी चीजे ध्यान मे आती है । जो हमारे देश मे इस समय 337 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कई बैंकों के बीच मे, जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उनके बीच मे विभाजित किया गया है । इस प्रकार हमारे 240 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनमें हमारे लीड बैंक खुल गये है जिनकी सर्वे रिपोर्ट अभी पिछले साल की तैयार है और अभी थोड़े से बाकी है कोई दो प्रतिशत जहा कि सर्वे का काम हो रहा है । वहा भी शीघ्र ही सर्वे के आधार पर और इसी नीति के आधार पर यह खोल दिए जाएंगे ।

MR SPEAKER : Next question.

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : अध्यक्ष महोदय, जो बैंकों की शाखाएं खोली गई है.....

MR SPEAKER : I do not take notice of Members who speak while sitting.

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : **

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर । मैंने आप को इजाजत नहीं दी । यह रेकार्ड पर नहीं आएगा जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगा तो क्या फायदा आप के बोलने से ?

पर्यटकों को प्रदान की जाने वाली परिवहन एवं मनोरंजन सुविधाओं पर किया गया व्यय

*604. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग पर्यटकों को परिवहन एवं मनोरंजन सुविधायें देता है ;

(ख) यदि हां, तो 1969, 1970 और 1971 में, अलग अलग, इन सुविधाओं पर कुल कितना व्यय किया गया ; और

(ग) इस सम्बन्ध में पर्यटकों के लिये बनाये गये विभिन्न कार्यक्रम क्या है ?

THE MINISTER OF STAE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. SAROJINI MAHISHI) : (a) and (c). The Department of tourism has taken the following measures for providing transport and entertainment facilities to the tourists :—

(1) Transport operators are accorded approval to assist them in maintaining vehicles and services of the standard required.

(2) Vehicles are obtained and made available to State Governments and the ITDC for operation.

(3) The India Tourism Development Corporation operates a large fleet of vehicles and organises evening entertainment and cultural programmes.

(4) *Son-et-lumiere* shows are being progressively organised.

(5) Occasional support is extended to cultural bodies to provide evening entertainment.

(6) Support has been extended on occasions to State Governments for organising tourist festivals.

(b) The expenditure of the Department of Tourism is as follows :—

	1969-70	*1970-71*	*1971-72*
		(*Rs. in lakhs.*)	
Transport	7.27	Nil	7.66
Entertainment	3.44	21.385	9.585
	10.71	21.385	17.245

श्री मूलचन्द डागा : आप ने यह बतलाया है कि 1969-70 में 3 लाख 44 हजार रुपया खर्च हुआ है और एक साल के बाद ही 21 लाख 38 हजार रुपया खर्च हुआ है तो आप यह बतलाइए कि कौन कौन सी ऐसी सांस्कृतिक इकाइयां हैं जिनको आप ने सहायता दी और कौन कौन से मनोरंजन रखे गए?

डा० सरोजिनी महिषी : 1970-71 में करीब करीब 21 लाख रुपये एन्टरटेनमेंट पर खर्च हुए हैं उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आ गए और मनोरंजन भी आ गया । कई इंस्टीट्यूशंस को यह मदद दी गई है । गुजरात में साबरमती आश्रम में सोन-एट-लूमियेर पर करीब 12 लाख रुपया खर्च हुआ है । रेड फोर्ट में सोन-एट-लूमियेर का रिवीजन हो गया है, उस पर साढ़े चार लाख रुपया खर्च हुआ है और शालीमार में भी चल रहा है, उस पर 25 लाख रुपये खर्च होने का अन्दाजा है, उसमें से कुछ हिस्सा दिया गया है । मनोरंजन के कार्यक्रम में सबसिडी दी जाती है और केरल में कत्थकली डांस वगैरह जो दिखाते रहते हैं आने वाले टूरिस्ट्स को उनको भी 500 से हजार रुपये तक सहायता दी गई है ।

श्री मूलचन्द डागा : आपने यह बतलाया कि कई राज्यों को भी इसके लिये सहायता

** Not recorded.